



भाजपा ने गुरुवार को जयपुर में अल्बर्ट हॉल से बड़ी चौपड़ तक भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम को समर्पित तिरंगा यात्रा निकाली। यात्रा का न्यू गेट, बापू बाजार, सांगानेरी गेट, जौहरी बाजार, जामा मस्जिद पर पुष्प वर्षा के साथ स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, उप मुख्यमंत्री दीपा कुमारी सहित भाजपा नेता, पदाधिकारी, सांसद, विधायक, विद्यार्थी, महिलाएं-बुजुर्ग इय तिरंगा यात्रा में शामिल हुए।

जोश व उत्साह का माहौल था जयपुर की तिरंगा यात्रा में

यह नया भारत है, जहाँ आतंकियों की मदद करने वालों को करारा जवाब दिया जाता है- मुख्यमंत्री

जयपुर, 15 मई। भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम को समर्पित तिरंगा यात्रा जयपुर में गुरुवार को निकाली गई। तिरंगा यात्रा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, उप मुख्यमंत्री दीपा कुमारी सहित, भाजपा नेता, पदाधिकारी, सांसद, विधायक, समाज के बुद्धिजीवी वर्ग के लोग, विद्यार्थी, महिलाएं-बुजुर्ग शामिल हुए। तिरंगा यात्रा अल्बर्ट हॉल से शुरू होकर न्यू गेट, बापू बाजार, सांगानेरी गेट होते हुए बड़ी चौपड़ पर संपन्न हुई। यात्रा के दौरान रास्तों में फूलों की वर्षा के साथ देशभक्ति का माहौल देखने को मिला। जामा मस्जिद पर मुस्लिम समुदाय ने भी यात्रा का स्वागत कर गंगा-जमुनी तहजीब की मिसाल पेश की।

तिरंगा यात्रा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, “पहलगाव हमले के बाद देशवासियों के मन में जो

■ **जौहरी बाज़ार में जामा मस्जिद पर मुस्लिम समुदाय ने तिरंगा-यात्रा का भव्य स्वागत किया। सांगानेरी गेट पर हनुमान मंदिर को तिरंगे की पौशाक में सजाया गया।**

आक्रोश था, उसे हमारी सेना ने आतंकियों के अड्डों पर हमला कर शांत किया। यह नया भारत है, जहां आतंकियों की मदद करने वालों को करारा जवाब दिया जाता है।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने तिरंगा यात्रा को संबोधित करते हुए कहा कि यह यात्रा किसी राजनीतिक दल की नहीं, बल्कि भारतीय सेना के सम्मान में प्रदेश के हर नागरिक की है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रभक्ति, पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए समान रूप से जरूरी है। कांग्रेस नेताओं को भी इसमें शामिल होना चाहिए था। उन्होंने कहा कि तिरंगा

यात्रा प्रदेश के सभी संभागों, जिलों और विधानसभा क्षेत्रों में निकाली जाएगी। उपमुख्यमंत्री दीपा कुमारी ने तिरंगा यात्रा को संबोधित करते हुए कहा कि सेना ने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ने वालों को मिट्टी में मिला दिया। भारत ने दुनिया को दिखा दिया है कि “टैरर” और “टॉक” एक साथ नहीं चल सकते। तिरंगा यात्रा के दौरान सांगानेरी गेट, जौहरी बाजार, और जामा मस्जिद पर लोगों ने भारत माता के जयकारे लगाए और यात्रा पर पुष्पवर्षा कर स्वागत किया। इस दौरान “पाकिस्तान मुर्दाबाद” के भी नारे

लगाए गए।

तिरंगा यात्रा में स्कूली छात्र-छात्राएं भी देशभक्ति गीतों पर झूमते नजर आए। सांगानेरी गेट के पास स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर को तिरंगे की पौशाक से सजाया गया था।

तिरंगा यात्रा कार्यक्रम मंच पर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अरूण चतुर्वेदी, अशोक परनामी, सीपी जोशी, सांसद मंजू शर्मा, भाजपा प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी, सरकार के मंत्री जोगाराम पटेल, विधायक कालीचरण सराफ, पूर्व सांसद रामचरण बोहरा, बालमुकुंदाचार्य, तिरंगा यात्रा प्रदेश समन्वयक भूपेन्द्र सैनी और अंकित चेची, भाजपा जयपुर जिलाध्यक्ष अमित गोयल, दक्षिण जिलाध्यक्ष राजेश गुर्जर, उत्तर जिलाध्यक्ष सुरेश सैनी, मेयर कुसुम यादव, उप महापौर पुनीत कर्नावट सहित, प्रदेश पदाधिकारी उपस्थित थे।

‘भारत अमेरिका से आयातित सामान पर कुछ भी टैरिफ नहीं लगायेगा’

–अंजन रॉय–

–राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो–

नई दिल्ली, 15 मई। भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका को “नो टैरिफ” (शुल्क-मुक्त) व्यापार समझौते की पेशकश की है। यह दोनों देशों के बीच व्यापार संबंधों में सबसे अद्वितीय घटना हो सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप का दावा है कि भारत ने अमेरिकी वस्तुओं पर ज़ीरो टैक्स का वादा किया है।

ट्रंप ने दावा किया था कि भारत और पाकिस्तान के बीच चार दिन की सशस्त्र झड़प उस समय सुलझी जब उन्होंने दोनों देशों को व्यापार का प्रस्ताव दिया। अपने विशिष्ट बेपरवाह अंदाज़ में उन्होंने कहा था, “तुम युद्ध रोको, मैं व्यापार करूंगा। अगर लड़ाई नहीं रुकी, तो व्यापार नहीं होगा।”

अब डॉनल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि भारत ने अमेरिका को ऐसे द्विपक्षीय व्यापार समझौते (बायलेटल ट्रेड) की पेशकश की है जिसमें कोई भी शुल्क नहीं होगा। ब्रिटेन के साथ फ्री ट्रेड का एक कमज़ोर सा समझौता होने के बाद

ट्रम्प ने यह अजीबोगरीब वक्तव्य दिया, जो कतई सम्भव नहीं लगता

अमेरिका के लिए यह पहला बड़ा व्यापार सौदा हो सकता है।

अगर यह सच है, तो यह “मुक्त व्यापार समझौते” का एक अनोखा उदाहरण होगा जहाँ दो देशों के बीच बिना किसी शुल्क के व्यापार किया जाएगा। सामान्यतः, मुक्त व्यापार समझौते इस प्रकार के नहीं होते हैं।

जब मुक्त व्यापार समझौते किए भी जाते हैं, तो ये केवल शुल्क ही नहीं, बल्कि, व्यापार और मर्चेंडाइज़ स्ट्रेण्डर्ड्स (माल मानक) की संपूर्ण प्रणाली को विस्तार से शामिल करते हैं। अतः, उदाहरण के लिए, एक मुक्त व्यापार समझौता यह निर्धारित करता है कि किसी निर्यात किए गए उत्पाद में स्थानीय सामग्री की कितनी हिस्सेदारी होनी चाहिए।

इसके अलावा, कुछ टैक्स और शुल्क भी होते हैं जो घरेलू कंपनियों द्वारा किसी वस्तु के

■ **उदाहरण के लिये, जब आयातित सामान पर कुछ भी टैरिफ नहीं होगा, तो, देश में निर्मित सामान स्वतः ही बाहर से आयातित सामान से महंगा हो जायेगा। जैसे, भारत में निर्मित किसी भी सामान पर, निर्माता को जी.एस.टी. देना अनिवार्य होता है। दूसरी ओर आयातित सामान पर कोई जी.एस.टी. नहीं लगता, क्योंकि, आयातित वस्तुओं का निर्माण भारत में ही नहीं रहा। अतः अनायास ही स्वदेशी निर्मित सामान, आयातित सामान से जी.एस.टी. टैक्स की वैल्यू जितना महंगा अपने आप हो गया।**

■ **अतः, “नो टैरिफ” एग्रीमेंट लागू करने के लिये काफी मेहनत करनी होती है, काफी बारीकी से अध्ययन करके, “काउन्टर प्रोवेलिंग” टैक्स का प्रावधान करना होता है।**

निर्माण में चुकाए जाते हैं। इन घरेलू शुल्कों के लिए समायोजन प्रावधान आवश्यक होते हैं,

अन्यथा घरेलू निर्माता अनुचित व्यापार का शिकार हो सकते हैं।

उदाहरण के लिए, भारतीय घरेलू उत्पादकों को जीएसटी, वस्तु एवं सेवा कर, अनिवार्य रूप से चुकाना होता है। यदि भारतीय निर्माता जीएसटी चुकाते हैं और विदेशी निर्माता बिना किसी टैक्स के भारतीय बाजार में प्रवेश करते हैं, तो घरेलू निर्माता उस जीएसटी के कारण प्रतिस्पर्धा में पिछड़ जाते हैं।

डॉनल्ड ट्रंप द्वारा बिना तथ्यों के किए जाने वाले दावे व्यापार और वाणिज्य की इन जटिलताओं को सामान्यतः अनदेखा करते हैं।

ऐसे मामलों में, जहाँ टैक्स का प्रभाव अलग-अलग होता है, वहाँ आयातित वस्तुओं पर भी वही घरेलू कर लगाए जाते हैं जो घरेलू वस्तुओं पर लागू होते हैं।

ये “काउन्टरवैलिंग टैक्स” (प्रतिस्तुलन कर) होते हैं, जो अंतिम कीमत पर टैक्स का प्रभाव बराबर रखने के लिए होते हैं।

भारत और अमेरिका की टीमें फिलहाल कुछ व्यापार समझौतों को अंतिम रूप देने के लिए बातचीत कर रही हैं, खासकर अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा हाल ही में घोषित टैरिफ के बाद।

ट्रंप के शासन में अमेरिका ने सभी आयातों पर 10 प्रतिशत का व्यापक शुल्क लगाया था। इसके अतिरिक्त, अमेरिका ने रैसिप्रोकल टैक्सज़ेड (प्रतिस्पर्धात्मक कर) की घोषणा की थी, जो अमेरिकी वाणिज्य विभाग द्वारा तैयार किए गए किसी फॉर्मूले पर आधारित होते हैं।

ये टैक्स अमेरिकी प्रशासन द्वारा मनमाने ढंग से लगाए गए थे। उदाहरण के लिए, चीन के मामले में, अमेरिका ने कुल मिलाकर 145 प्रतिशत तक के शुल्क लगा दिए थे। चीन ने भी उसी स्तर पर प्रतिशोध लिया। इन प्रतिशोधी कार्रवाइयों के बाद, चीन और अमेरिका अब अपने टैरिफ को अधिक व्यवहारिक स्तरों पर लाने के लिए बातचीत कर रहे हैं।

अमेरिका ने चीन से आयात पर अपने शुल्क को घटायकर लगभग 30 प्रतिशत कर दिया है, (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

जज 100 किलोमीटर गए दुष्कर्म पीड़िता को राहत देने

जयपुर, 15 मई। कोटपूतली-बहरोड में चिकित्सकों ने एक नाबालिग रेप पीड़िता का गर्भपात करने से इनकार कर, उन्हें हाईकोर्ट का आदेश लाने को कहा। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को

■ **कोटपूतली-बहरोड में नाबालिग रेप पीड़िता का चिकित्सकों ने गर्भपात करने से मना कर दिया था और हाई कोर्ट का आदेश लाने को कहा था, इस पर विधिक सेवा प्राधिकरण ने एडीजे पवन जीनवाल को तत्काल वहाँ भेजा।**

मामले की जानकारी मिलने पर सदस्य सचिव हरिओम अत्रि ने गंभीरता दिखाते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एडीजे पवन जीनवाल को जयपुर से तत्काल सौ किलोमीटर दूर अस्पताल (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

लड़ाई केरल के मुख्यमंत्री के पद की है

थरूर को रेस से बाहर करने के लिये, के.सी. वेणुगोपाल ने जयराम को मोहरा बनाया है

–रेणु मित्तल–

–राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो–

नई दिल्ली, 15 मई। शशि थरूर दुखी और असमंजस में हैं। वह कांग्रेस पार्टी छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन उन्हें लगता है कि उन्हें मजबूर किया जा रहा है, क्योंकि, के.सी. वेणुगोपाल के नेतृत्व वाला एक गुट ऐसे हालात बना रहा है कि उन्हें कांग्रेस छोड़नी पड़े।

यह सारा विवाद केरल के मुख्यमंत्री पद को लेकर है, जिसमें वेणुगोपाल का पूरा ध्यान केवल केरल की कुर्सी पर केंद्रित है।

रमेश चेन्नोथला एक मजबूत दावेदार हैं, जिन्हें लगता है कि मुख्यमंत्री बनने का उनके लिए यह आखिरी मौका है। वह पार्टी में लोकप्रिय हैं और अधिकांश विधायक उनका समर्थन करते हैं।

इस दौड़ में शशि थरूर, मुख्य विपक्षी नेता सतीशन और करुणाकरन के बेटे मुरलीधरन भी शामिल हैं।

रमेश चेन्नोथला कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड्गे के काफी नजदीकी हैं, जबकि वेणुगोपाल का राज्य में कोई विशेष आधार नहीं है, लेकिन उनकी ताकत राहुल गांधी है।

केरल कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद को

■ **जयराम रमेश, वेणुगोपाल को खुश करने के लिये, बार-बार शशि थरूर को टारगेट बना रहे हैं।**

■ **राहुल गांधी को वेणुगोपाल पर पूर्ण विश्वास है, अतः वे वेणुगोपाल-जयराम रमेश की थरूर को पार्टी से बाहर निकलवाने की साजिश से पूरी दूरी बनाते हुए, “जो चल रहा है, चलने दो” की नीति से आगे बढ़ रहे हैं।**

■ **जयराम रमेश ने यह बात फैलायी कि सी.डब्ल्यू.सी. की बैठक में शशि थरूर को चेतावनी दी गई कि वे ऐसे वक्तव्य न दें, जिससे पार्टी को राजनीतिक हानि हो रही है। पर, गहराई से जाँच करने से ज्ञात हुआ कि बैठक में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। जयराम के कुप्रचार से शशि थरूर जरूर विचलित हो गये और सी.डब्ल्यू.सी. की बैठक के बारे में ऑफिशियल स्पष्टीकरण जारी करना पड़ा।**

लेकर जबरदस्त घमासान छिड़ चुका है और जयराम रमेश के कारण अब यह विवाद कांग्रेस कार्यसमिति (सी.डब्ल्यू.सी.) तक पहुँच गया है। जयराम रमेश शशि थरूर को पार्टी से बाहर करने के लिए के.सी. वेणुगोपाल को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं।

सी.डब्ल्यू.सी. की बैठक में जयराम रमेश ने एक टिप्पणी की कि कुछ लोगों ने

“लक्ष्मण रेखा” पार कर दी है। उनका इशारा शशि थरूर के उन बयानों की ओर था जिन्हें सरकार और नरेन्द्र मोदी के समर्थन के तौर पर देखा जा रहा है।

हालाँकि किसी का नाम नहीं लिया गया और इस मुद्दे पर सी.डब्ल्यू.सी. में कोई चर्चा नहीं हुई और पार्टी नेतृत्व ने शशि थरूर को इस पर कोई फटकार भी नहीं लगाई।

ब्रीफिंग के दौरान एक सवाल के जवाब में जयराम रमेश ने टिप्पणी की कि थरूर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता नहीं हैं और न ही वह पार्टी की ओर से बोलते हैं।

बाद में उन्होंने मीडिया को जानकारी दी कि नेतृत्व ने थरूर को फटकार लगाई और कहा कि वह सरकार के समर्थन में बयान न दें जैसा कि वह करते रहे हैं। जब उनसे पूछा गया कि क्या थरूर के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी, क्योंकि उन्होंने “लक्ष्मण रेखा” पार की है, तो उन्होंने “नहीं” में जवाब दे दिया और कहा कि अब कुछ नहीं होगा।

यह साफ तौर पर विरोधाभास को दर्शाता है। अगर वाकई में लक्ष्मण रेखा पार हुई है, तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? लेकिन कौन जानता है कि वह असल में क्या कहना चाह रहे थे।

अगले दिन मलयालम अखबारों और चैनलों में बड़ी-बड़ी सुर्खियों के साथ खबरें छपीं कि थरूर को पार्टी नेतृत्व ने फटकार लगाई है।

शशि थरूर को सफाई देनी पड़ी कि सी.डब्ल्यू.सी. में ऐसा कुछ नहीं हुआ और वह कुछ मुद्दों पर सरकार का समर्थन उसी तरह कर रहे हैं जैसे कि उनकी पार्टी ने (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

‘किराना हिल्स से ‘रेडियोएक्टिव लीकेज’ नहीं हुआ’

इन्टरनैशनल एटॉमिक एनर्जी एजेन्सी ने साफ स्पष्टीकरण दिया कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर वैपन्स स्टोरेज सुविधा से कोई “रेडिएशन लीक” नहीं हुई

–श्रीनन्द झा–

–राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो–

नई दिल्ली, 15 मई। ऐसी अटकलें लगाई जा रही थीं कि भारतीय मिसाइलों के बाद, किराना हिल्स-स्थित पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियार स्टोर से रिसाव हो रहा है, लेकिन इन्टरनैशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी (आईएईए) के स्पष्टीकरण के बाद, इन सारी अटकलों और चर्चाओं पर विराम लग गया है। आईएईए ने कहा है कि पाकिस्तान की किसी भी न्यूक्लियर फेसिलिटी से कोई रेडिएशन लीकेज नहीं हो रही है।

इन अटकलों को उस समय बल मिला था, जब पाकिस्तानी एयरस्पेस में अमेरिकन बीचक्राफ्ट बी 350 एरियल मैजिंग सिस्टम (एमएस) ने लीकेज डिटेक्ट किया। जानकारी मिली थी। यह एयरक्राफ्ट अमेरिकन डिफेंसिबल एनर्जी फ्लीट का हिस्सा है, जो

■ **यह अफवाह, इसलिए फैली कि यू.एस. बीचक्राफ्ट बी 350, को पाकिस्तान की एयर स्पेस में देखा गया था। यह हवाई जहाज, ऐसे रेडियोएक्टिव प्रदूषण (कन्टैमिनेशन) की पहचान करने के काम आता, जो अचानक लीकेज से फैल गया हो।**

■ **अफवाह को इस बात से भी पुष्टि मिली कि मिस्र से एक हवाई जहाज, “बोरोन” लेकन पाकिस्तान आया था। “बोरोन”, रेडियोएक्टिव एमिशन पर नियंत्रण पाने के लिये काम में लाया जाता है।**

■ **इन अफवाहों के कारण आई.ए.ई.ए. के प्रवक्ता को वक्तव्य देना पड़ा कि किराना हिल्स में कोई रेडियोएक्टिव लीक नहीं हुई।**

आपातकालीन स्थितियों में रेडियोएक्टिव कन्टैमिनेशन को चिन्हित करने के लिये तैयार किया गया है। ये अफवाहें उस समय फिर जोर पकड़ गईं,

जब अमेरिकन डिफेंसिबल ऑफ स्टेट के प्रिंसिपल डिप्टी स्पोक्सपर्सन टॉमी पिगांट हाल ने ही की एक प्रेस –ब्रीफिंग (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

विचार बिन्दु

आपति मनुष्य बनाती है और संपत्ति राक्षस। –विक्टर ह्यूगो

क्या जातिगत आरक्षण के चक्रव्यूह को तोड़ने का कोई संवैधानिक मार्ग है?

संविधान निर्माताओं ने संविधान में व्यवस्था दी है कि किसी के साथ जाति, रंग, धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं होगा। सभी को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा अपने धर्म के अनुसार आराधना, पूजा व उसे मानने की स्वतंत्रता होगी। प्रत्येक नागरिक को जीने का मूल अधिकार होगा। संविधान में सामाजिक न्याय को आर्थिक व राजनीतिक न्याय से प्रथम स्थान यानी प्रायोरिटी दी गई थी। दलित के साथ किये गये अन्याय को यह क्षतिपूर्ति का तथा समानता के अधिकार की ओर उठाया हुआ कदम था। यह स्पष्ट है कि सामाजिक न्याय का संबंध, आर्थिक न्याय से नहीं है। वर्तमान में सामाजिक न्याय के इस अधिकार के कारण पिछड़ों का एक वर्ग इस आरक्षण के कारण अब पिछड़े नहीं रहे वे क्रिमिलेयर आ चुके हैं, यानी आरक्षण से बाहर हो गये। किन्तु यह प्रक्रिया इतनी धीमी रही कि 95% अभी भी पिछड़े ही हैं। आरक्षण आवश्यक था और इसे अब तक पूरी हो जाना चाहिये था; किन्तु आरक्षण की मांग का विस्तार हो रहा है। आरक्षण की मांग जाति, उपजाति में उठाई जा रही है।

जातिगत आरक्षण को लगभग अभी पार्टियों ने बुरा विचार माना है। सत्ताधारी पार्टी भाजपा जातीय गणना को विभाजनकारी व विध्वंसकारी तथा खतरनाक बता चुकी है; किन्तु वही पार्टी इसका स्वागत कर रही है। कांग्रेस से कहा भाजपा ने उसका विचार ही चुरा लिया है। वस्तुतः यदि आरक्षण के इतिहास को देखा जावे तो हमें कालेकर कमीशन की रिपोर्ट को समझना होगा। भारत के गृहमंत्री ने कहा है कि यह सच है कि कांग्रेस Anti-Reservation है। कांग्रेस ने कमीशन की रिपोर्ट पर अमल नहीं होने दिया। इस रिपोर्ट में भारत के पहले इस बैकवर्ड कमीशन ने 70% रिजर्वेशन की बात की। यह 1953 की घटना है। इस बावत राजनैतिक पार्टी के नेताओं में विचारों की भिन्नता है।

इसमें काई शक नहीं है कि देश में कई जगह जातियों के आंकड़े इकट्ठे किये गये हैं, किन्तु उस पर कोई कदम नहीं उठाया गया। कहते हैं भाजपा के पास आंकड़े हैं, किन्तु उसे सार्वजनिक नहीं किया गया। रोहिणी आयोग भी गठित हुआ किन्तु उसने क्या किया, किसी को पता नहीं है। कोई विश्वास साथ यह नहीं कह सकता कि इस आंकड़ों की क्या उपयोगिता होगी। राहुल गांधी ने आरक्षण की सीमा 50% से अधिक बढ़ाने की बात कर रहे हैं, इसके लिये तो संवैधानिक संशोधन लाना होगा। आरक्षण का अर्थ है सरकारी नौकरी परन्तु सरकार के पास क्या नौकरियां हैं? कई प्रकार के विचार वाले लोग इस देश में हैं।

आरक्षण की समस्या का लम्बा इतिहास है। वर्ष 1978 में कपूरी ठाकुर ने बिहार में आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण की घोषणा की थी, जिसके फलस्वरूप राजनीति में एक तुफान आ गया था। इस पर विचार करने व अनुशंसा देने के हेतु मंडल आयोग का गठन हुआ। मंडल आयोग ने अपनी सिफारिशों के आधार पर 1971 में जनगणना और जाति आधारित गणना के लिये पिछड़ेपन को अपनाया। उस समय आर्थिक पिछड़ेपन की बात छोड़ दी गई और उन धर्मों को भी अलग कर दिया था जहां जाति व्यवस्था नहीं थी।

आरक्षण को समझने के लिये हमें विधान निर्मात्री सभा की कमेटी के कार्य को समझना होगा और संविधान के अनुच्छेद 334 को स्वरूप देने के प्रक्रिया का अध्ययन करना होगा। विधान निर्मात्री सभा के चेयरपर्सन बाबा साहब ड।अम्बेडकर थे। संविधान के अनुच्छेद 334 में यह व्यवस्था दी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की पार्लियामेंट व असेम्बली की सीटें कैसे निर्धारित की जावेंगी। अनुच्छेद 334 जो 26.01.1950 को संविधान में था उसके अनुसार यह प्रावधान दिनांक 29.01.1960 को स्वतः ही समाप्त हो जाने की व्यवस्था थी। एक प्रकार से यह संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर का भाग था, जिसमें संशोधन नहीं हो सकेगा। आश्चर्य तो इस बात का है कि संविधान के मूल प्रारूप में (ड्राफ्ट) में यह प्रावधान ही नहीं था। बाबा साहब इस प्रावधान के पक्ष में नहीं थे। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति ने बाबा साहब से प्रतिवेदन दिया प्रार्थना की, इस पर बड़ी भिन्नत के बाद यह आरक्षण केवल 10 वर्ष तक के लिये रखा गया जो समयवाधि के बाद स्वतः ही Sunset Laws के अनुसार समाप्त होना था। बाबा साहब ने तो यहां तक कहा था, जो संसद की कार्यवाही के रेकार्ड से अभिव्यक्त है कि 10 वर्ष के बाद एक दिन भी नहीं बड़ेगा। किन्तु दुर्भाग्य है कि संविधान की मर्यादा के प्रतिकूल प्रत्येक 10 वर्ष बाद इसे 20, 30, 40, 50, 60, 70 व 80 वर्ष संविधान में संशोधन से कर दिया जाता है जो सर्वथा असंवैधानिक है। इस समन्वय में चुनौती देने वाली याचिकायें वर्षों से सुप्रीम कोर्ट में जैरकार हैं, किन्तु सुनवाई नहीं हो रही है। राजस्थान

आजादी के 75 वर्षों बाद भी केवल मुठ्ठी भर लोगों का पिछड़ापन समाप्त हुआ है, यह देश के शासन के लिये चिन्ता का विषय होना चाहिये। संविधान की भावना तथा सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों को हमें जनहित, समाजहित व देशहित में समझना है, स्वीकार करना है तथा जातिगत आरक्षण के चक्रव्यूह को तोड़ने का कोई संवैधानिक सुगम, सरल व मान्य मार्ग ढूंढना होगा।

हाईकोर्ट में भी याचिका पेश की थी, उसे भी सुप्रीम कोर्ट भेज दिया गया। यदि यह प्रावधान लागू होता तो 1960 के बाद की राजनीति में नया रूप आ जाता। आरक्षण के विषय में संविधान पीठ के कई निर्णय हुये हैं। इनका सार है कि अनुच्छेद 16(4), (4ए) (4बी), स्वयं में मूल अधिकार नहीं है केवल Enabling (कार्यकारी) प्रावधान है तथा सरकार आजादी के इतने वर्षों के बाद आरण देने के बाध्य नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 16(4) में यह व्यवस्था है कि पिछड़ों के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में पर्याप्त नहीं है, आरक्षण दे सकती है, किन्तु

कौन पिछड़ा है तथा प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है इसके लिये पर्याप्त व प्रमाणिक आंकड़े अति आवश्यक हैं। यदि राज्य पिछड़े वर्गों को नियुक्ति के आरक्षण पर विचार करती है तो प्रत्येक केस में अनिवार्य कारणों से प्रावधान बनाने से पूर्व संख्यात्मक आंकड़ों से साबित करना होगा कि (1) क्या सकल प्रशासनिक दक्षता की सुरक्षा को तो कोई खतरा नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि यदि सरकार आरक्षण संबंधित प्रावधान बनाती है या अधिकार का प्रयोग करती है तो उसे पानी की पालना करना अनिवार्य होगा। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि (1) किसी भी स्तर पर आरक्षण 50% से अधिक नहीं होगा (2) क्रिमिलेयर को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा (3) ओबीसी, एससी एवं एसटी का उपवर्गीकरण यथावत रहना होगा। बैकलॉग नियम 3 वर्ष से अधिक का नहीं होगा (4) चूंकि अनुच्छेद 16(4) (4ए) (4बी) ही प्रवाहित हुये हैं, अतः पदोन्नति में भी आरक्षण के प्रावधान बनाने के लिये वे ही शर्त लागू करना अनिवार्य होगा।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष क्रिमिलेयर का प्रश्न कई बार उठाया गया है और यह सिद्धान्त प्रतिपादित हुआ है कि जो क्रिमिलेयर के हैं उन्हें अनुसूची से बाहर होना चाहिये। ऐसे लोगों का जस्टिस कृष्णा अय्यर ने क्रिमिलेयर के शब्द से स्टेट ऑफ केरल बनाम एन एम थोमस 1976(2) एससीसी 310 में सम्बोधित किया है। एम नागराज बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया 2006 (8) एससीसी 1, यूपी पावर कॉर्पोरेशन बनाम राजेशकुमार 2012 (7) एससीसी अशोक कुमार ठाकुर के केस 2008 (6) एससीसी आदि निर्णयों में इस सिद्धान्त को स्वीकार किया है। मलाई खाने वाले ये व्यक्ति अब आरक्षण का लाभ नहीं ले सकते। पिछड़े जो अब तक भी पूर्ववत पिछड़े ही हैं उन्हें सामाजिक न्याय मिलना चाहिये।

सर्वोच्च न्यायालय आर्थिक आधार पर भी आरक्षण हो सही माना है। यह आरक्षण सामाजिक पिछड़ेपन के आरक्षण के अतिरिक्त है। 103वें संविधान संशोधन से 2019 में आर्थिक रूप से कमजोरों के लिये 10: यह आरक्षण है।

सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस कृष्णा अय्यर के माध्यम से 1981 के निर्णय में यह अपेक्षा की है कि “राज्य की कार्य पद्धति की सफलता इससे आंकी जानी चाहिये कि वह ऐसी व्यवस्था पैदा करे कि अनुच्छेद 16(4) के अन्तर्गत आरक्षण की व्यवस्था ही समाप्त हो जावे। यह कोई महान मौलिक अधिकार नहीं है कि कुछ वर्ग शाश्वत रूप से अनन्त काल तक पिछड़े ही बने रहें। यह संविधान की मूल भावना के विरुद्ध है।”

इन्द्रा सहानी के केस के बाद कई निर्णयों में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता। राजस्थान में यह आरक्षण 50 प्रतिशत से कम है। सन 1992 से यह स्थिति बनी हुई है, कब तक सुप्रीम कोर्ट इस 50% की सीमा के विषय पर सुनती रहेगा। मुकदमों का अन्त होना चाहिये।

लेखक का अपना मत है कि उपरोक्त निर्णयों में तथा अन्य निर्णयों में माननीय सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ जो निर्णय दे चुकी है, उन पर 10 वर्ष तक पुनः विचार नहीं हो। देश का न्याय सत्ता, सरल व सुलभ हो तथा जिसमें स्थायित्व भी हो। क्रिमिलेयर के निर्णय, 50 प्रतिशत की सीमा के निर्णयों पर मोरिटेोरियम लगना चाहिये। हॉ जस्टिस जीवन रेड्डी के तथा तीन न्यायाधीशों के निर्णय के अनुसार जहां असाधारण परिस्थितियों हो वहां सीमा पार की जा सकती है; किन्तु वह भी उन लोगों के लिये जो मुख्य धारा से बाहर हैं तथा विपरीत परिस्थिति से घिरे हैं।

ऐसा माना जा रहा है कि केन्द्र सरकार की जो विचार धारा 2001, 2011 व 2020 में जनगणना व जातिगत जनगणना के संबंध में थी उसमें परिवर्तन आया है। जनगणना के साथ जातिगत जनगणना हो इस पर जनसभाओं में विचार मंथन होना चाहिये। जातियों की उपजातियों में जो अति पिछड़े हैं जिन्हें अब तक कोई महत्व नहीं मिला है और जो अरमानता व पिछड़ेपन के अधिभार से अधिक पीड़ित हैं, उनके बाबत आवश्यकता के अनुसार राष्ट्रीय नीति क्या हो, विचार हो। लोगों को सामाजिक न्याय मिले। ऐसी नीति बनाई जावे कि आने वाले 10 वर्षों में पिछड़ापन समाप्त हो। आजादी के 75 वर्षों बाद भी केवल मुठ्ठी भर लोगों का पिछड़ापन समाप्त हुआ है, यह देश के शासन के लिये चिन्ता का विषय होना चाहिये। संविधान की भावना तथा सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों को हमें जनहित, समाजहित व देशहित में समझना है, स्वीकार करना है तथा जातिगत आरक्षण के चक्रव्यूह को तोड़ने का कोई संवैधानिक सुगम, सरल व मान्य मार्ग ढूंढना होगा।

भगवान महावीर ने जगत को संदेश दिया था ‘अयातुला प्रया सु’ अर्थात् जगत् के प्रत्येक प्राणी को अपने समान देखो, जैसा तुम्हारा अस्तित्व है वैसा ही अन्य का भी मानो। यह प्रयास सह अस्तित्व की भावना को जागृत करेगा। हमारे संविधान का भी यही संदेश है।

–अतिथि सम्पादक,
पानाचन्द्र जैन
पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान हाई कोर्ट



राजेन्द्र मोहन शर्मा

भारत और पाकिस्तान के बीच हालिया तनाव और युद्धविराम ने दक्षिण एशिया की भू-राजनीतिक जटिलताओं को न केवल क्षेत्रीय, बल्कि वैश्विक मंच पर भी उजागर किया है। यह अल्पकालिक सैन्य टकराव, जिसे “आंशकों के साथे भी नहीं हुए सीज और आग भी ज्यों कि ल्यों” के रूप में देखा जा रहा है, ने भारत की सामरिक और कूटनीतिक परिपक्वता को प्रदर्शित किया, साथ ही पाकिस्तान की आर्थिक-सामरिक कमजोरियों को बेनकाब किया। पहलगाम आतंकी हमले से शुरू हुआ यह घटनाक्रम विभिन्न देशों की रणनीतियों, क्षेत्रीय गतिशीलता, और भारत की आंतरिक राजनीति को रेखांकित करता है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन, शशि थरूर के समर्थन, हाल के सर्वेक्षणों में उभरे जनसमर्थन, और नए अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों ने इस संकट में भारत की स्थिति को और मजबूत किया है। लेकिन पाकिस्तान की अविश्वसनीय आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्तता यथावत है अतः यह कहना कठिन है कि यह युद्ध विराम कब तक बना रहेगा। घटनाक्रम की पुष्टभूमि 22 अप्रैल 2025 को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को चरम पर पहुंचा दिया। इस हमले में 26 भारतीय नागरिकों की जान गई, भारत ने इस हमले के लिए पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठनों, विशेष रूप से लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद, को जिम्मेदार ठहराया। इसके बाद, पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा (एओसी) पर लगातार 11 दिनों तक संघर्ष विराम का उल्लंघन किया, जिसमें गोलीबारी और मोटार हमलों ने दोनों पक्षों में तनाव को और बढ़ाया।

भारत ने इस आक्रामकता का जवाब देने के लिए ‘ऑपरेशन सिंदूर’ शुरू किया, जो 2 मई 2025 को अपने

चरम पर पहुंचा। इस ऑपरेशन में भारतीय वायुसेना और थलसेना ने पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों, आतंकी अड्डों, और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के सात प्रमुख एयरबेस-नूर खान, रहमियार खान, स्कर्दू, मियांवाली, सरगोधा, कामरा, और मुल्तान-को पूरी तरह तबाह कर दिया। इसके अलावा, पाकिस्तान के रडार सिस्टम, हवाई रक्षा प्रणालियां और आतंकी प्रशिक्षण शिविरों को भी गंभीर क्षति पहुंची। इस कार्रवाई में लगभग 200 लोग मारे गए, जिनमें 100 से अधिक आतंकवादी शामिल थे। पाकिस्तान को अरबों रुपये की संपत्ति का नुकसान हुआ, जिसने उसकी पहले से ही कमजोर अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव डाला है। भारत की सैन्य और कूटनीतिक रणनीति भारत ने इस संकट में सैन्य शक्ति और कूटनीतिक संयम का शानदार संतुलन बनाए रखा।

भारतीय सेना की प्रवक्ता कर्नल सोफिया कुरैशी ने 8 मई 2025 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के दावों को खारिज किया, जिसमें उसने दावा किया था कि उसके जेएफ-17 लड़ाकू विमानों ने भारत के एस-400 और ब्रह्मोस मिसाइल बेस को नुकसान पहुंचाया। कुरैशी ने स्पष्ट किया कि भारत के सभी रक्षा ठिकाने और प्रणालियां सुरक्षित रहीं, और पाकिस्तान का प्रचार युद्ध पूरी तरह विफल रहा। उनकी प्रेस ब्रह्मोस की तैनाती, का अध्ययन करने के लिए किया। यह रणनीति चीन के उस दृष्टिकोण को दर्शाती है, जिसमें वह बिना संचर्ष के अपनी स्थिति को मजबूत करता है। तुर्क की आक्रामक बयानबाजी से भारत में बहुत आश्चर्य हुआ है। तुर्क ने पाकिस्तान का खुलकर समर्थन किया और भारत के खिलाफ आक्रामक बयानबाजी की। तुर्क के विदेश मंत्रालय ने 5 मई 2025 को एक बयान जारी कर कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के रुख का समर्थन किया, जिससे भारत-तुर्क संबंधों में तनाव बढ़ा है। यह तुर्क की क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं और पाकिस्तान के साथ गहरे संबंधों का परिणाम था। हालांकि, यह रणनीति तुर्क के लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है, क्योंकि भारत एक उभरती आर्थिक और सैन्य शक्ति है।

रूस की विश्वसनीय साझेदारी रूस ने इस संकट में भारत के साथ अपनी विश्वसनीय साझेदारी को और मजबूत किया। एस-400 और ब्रह्मोस

12 मई 2025 को राष्ट्र के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत की आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा, “टेरर और ठीक एक साथ नहीं हो सकते, टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं

चल सकते, पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते।” मोदी ने इस कार्रवाई को भारत की बहनों के सम्मान की रक्षा से जोड़ा, क्योंकि ऑपरेशन का नाम ‘सिंदूर’ भारतीय संस्कृति में नारी शक्ति का प्रतीक है। उन्होंने पाकिस्तान को चेतावनी दी कि युद्धविराम केवल सैन्य कार्रवाई को स्थगित करता है, और भारत उसकी हर गतिविधि पर नजर रखेगा। मोदी ने युद्धविराम के लिए अमेरिकी मध्यस्थता को स्वीकार करने के अपने फैसले का बचाव करते हुए कहा, “भारत शांति चाहता है, लेकिन अपनी संप्रभुता और सम्मान से समझौता नहीं करेगा।” उनके इस संबोधन ने न केवल भारत की एकजुटता को प्रदर्शित किया, बल्कि उनकी कूटनीतिक परिपक्वता को भी रेखांकित किया। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने ऑपरेशन सिंदूर की रणनीतिक योजना और निष्पादन की खुलकर प्रशंसा की। 13 मई 2025 को एक टेलीविजन साक्षात्कार में उन्होंने कहा, “संकट को बहुत अच्छे ढंग से संभाला गया। ऑपरेशन सिंदूर को मैं पूरे अंक देता हूं।” थरूर ने अपने हाल के लेख में लिखी पंक्ति-“यह युद्ध का युग नहीं है, लेकिन आतंकवाद का भी नहीं”-को मोदी के भाषण में शामिल होने पर प्रसन्नता जताई।

विश्लेषकों का मानना ​​है कि चीन ने इस तनाव का उपयोग भारत की रक्षा तैयारियों, विशेष रूप से एस-400 और ब्रह्मोस की तैनाती, का अध्ययन करने के लिए किया। यह रणनीति चीन के उस दृष्टिकोण को दर्शाती है, जिसमें वह बिना संचर्ष के अपनी स्थिति को मजबूत करता है। तुर्क की आक्रामक बयानबाजी से भारत में बहुत आश्चर्य हुआ है। तुर्क ने पाकिस्तान का खुलकर समर्थन किया और भारत के खिलाफ आक्रामक बयानबाजी की। तुर्क के विदेश मंत्रालय ने 5 मई 2025 को एक बयान जारी कर कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के रुख का समर्थन किया, जिससे भारत-तुर्क संबंधों में तनाव बढ़ा है। यह तुर्क की क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं और पाकिस्तान के साथ गहरे संबंधों का परिणाम था। हालांकि, यह रणनीति तुर्क के लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है, क्योंकि भारत एक उभरती आर्थिक और सैन्य शक्ति है।

रूस की विश्वसनीय साझेदारी रूस ने इस संकट में भारत के साथ अपनी विश्वसनीय साझेदारी को और मजबूत किया। एस-400 और ब्रह्मोस

जैसी रूसी तकनीकों ने भारत की रक्षा क्षमता को बढ़ाया। रूस के विदेश मंत्रालय ने 9 मई 2025 को एक बयान में आतंकवाद के खिलाफ भारत की कार्रवाई को जायज ठहराया, जिसने भारत की स्थिति को और मजबूत किया। ईरान की अप्रत्यक्ष भूमिका भी महत्वपूर्ण रही है। ईरान ने बलूचिस्तान में अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान पर दबाव बनाया। बलूच अलगाववादी आंदोलनों को समर्थन देकर ईरान ने पाकिस्तान की आंतरिक कमजोरियों को उजागर किया, जो भारत के लिए सामरिक लाभकारी रहा। यह भारत और ईरान के बीच बढ़ते सहयोग को दर्शाता है, विशेष रूप से क्षेत्रीय सुरक्षा और आतंकवाद के मुद्दों में। अमेरिका की मध्यस्थता इस संकट का निर्णायक मोड़ साबित हुई।

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 10 मई 2025 को भारत-पाकिस्तान युद्धविराम की घोषणा की और इसे अपनी कूटनीतिक जीत बताया। ट्रंप ने ट्रवीट किया, “भारत और पाकिस्तान के बीच शांति स्थापित करना मेरी सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है।” हालांकि, भारत ने अपनी शर्तों पर युद्धविराम स्वीकार किया, जिसमें पाकिस्तान से आतंकी गतिविधियों पर रोक लगाने की मांग शामिल थी। इस मध्यस्थता ने भारत के दशकों पुराने रुख-कश्मीर पर तीसरे पक्ष की मध्यस्थता अस्वीकार-को चुनौती दी। कई विश्लेषकों ने सवाल उठाया कि भारत ने इस मुद्दे पर अमेरिका की मध्यस्थता की अनुमति क्यों दी। यह कदम भारत की आंतरिक राजनीति में बहस का विषय बना, क्योंकि कुछ ने इसे भारत की कूटनीतिक स्वायत्तता पर सवाल के रूप में देखा। आंतरिक राजनीतिक गतिशीलता असदुद्दीन ओवैसी की भूमिका की दृष्टि से उल्लेखनीय रही। आईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान के धार्मिक प्रचार को नाकाम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

न्यूज 18 के मई 2025 सर्वेक्षण के अनुसार, 68% भारतीयों ने ऑपरेशन सिंदूर को आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कदम माना, और 72% ने मोदी की कूटनीतिक-सैन्य रणनीति की प्रशंसा की। इंडिया टुडे के एक अन्य सर्वेक्षण में 65% लोगों ने कहा कि मोदी का संबोधन राष्ट्रीय गौरव को बढ़ाने वाला था। यह समर्थन भाजपा के भीतर मोदी की स्थिति को और मजबूत करता है, हालांकि अमेरिका की मध्यस्थता पर

कुछ असंतोष भी उभरा है। यह संकट भारत की सामरिक और कूटनीतिक ताकत को उजागर करता है, लेकिन कई सवाल अनुत्तरित हैं। अमेरिका की मध्यस्थता –भारत ने कश्मीर जैसे द्विपक्षीय मुद्दे में अमेरिका को मध्यस्थता की अनुमति क्यों दी? यह भारत की कूटनीतिक स्वायत्तता पर सवाल उठाता है। युद्धविराम की घोषणा –युद्धविराम की घोषणा भारत के बजाय ट्रंप ने क्यों की? क्या यह भारत की कूटनीतिक रणनीति में चूक थी? मोदी की छवि-क्या यह कदम मोदी की अजेय छवि को प्रभावित करेगा?

हालांकि सर्वेक्षण उनके पक्ष में हैं, लेकिन कुछ आलोचकों का मानना ​​है कि यह कदम उनकी पार्टी के भीतर असंतोष को जन्म दे सकता है। इस संकट ने पाकिस्तान की आर्थिक और सामरिक कमजोरियों को उजागर किया। उसकी अर्थव्यवस्था, जो पहले से ही आईएमएफ के कर्ज पर निर्भर है, इस नुकसान से और कमजोर हुई। दूसरी ओर, भारत ने अपनी सैन्य और कूटनीतिक ताकत को प्रदर्शित कर वैश्विक मंच पर अपनी स्थिति को मजबूत किया। भारत को भविष्य में कई चुनौतियों का सामना करना होगा। सबसे पहले, उसे अपनी रक्षा तैयारियों को और मजबूत करना होगा, विशेष रूप से चीन जैसे प्रतिद्वंद्वियों के सामने। दूसरा, कूटनीतिक स्तर पर भारत को यह सुनिश्चित करना होगा कि कश्मीर जैसे मुद्दों पर तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को रोका जाए। तीसरा, आंतरिक स्तर पर सामाजिक एकता और राजनीतिक स्थिरता को बनाए रखना महत्वपूर्ण होगा। निष्कर्ष:ऑपरेशन सिंदूर और युद्धविराम ने भारत को एक उभरती वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित किया। मोदी के संबोधन, थरूर के समर्थन, और जनसमर्थन ने भारत की एकजुटता को रेखांकित किया। पाकिस्तान की हार और क्षेत्रीय शक्तियों की भूमिकाओं ने दक्षिण एशिया की जटिल गतिशीलता को उजागर किया। हालांकि, अमेरिका की मध्यस्थता और युद्धविराम की घोषणा से जुड़े सवाल भविष्य की कूटनीति को प्रभावित कर सकते हैं। भारत को संयम और शक्ति का संतुलन बनाए रखते हुए क्षेत्रीय और वैश्विक चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना करना होगा।

–राजेन्द्र मोहन शर्मा,
वरिष्ठ साहित्यकार,
शिक्षाविद, और चिंतक

भीलवाड़ा शहर के कई इलाकों दस दिन से जल आपूर्ति पूरी तरह ठप, लोग परेशान

भीषण गर्मी के बीच गहराने लगा जल संकट, आक्रोशित शहरवासियों ने प्रदर्शन किया

भीलवाड़ा, (निसं)। शहर के कई इलाकों में भीषण गर्मी के बीच गत दस दिन से जल आपूर्ति पूरी तरह ठप है, जिससे आमजन को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने बताया कि शहर की कई कॉलोनियों के लोग पानी की समस्या से परेशान हो रहे हैं। शहर की सुभाष नगर, राजपूत कॉलोनी, पालड़ी रोड, देवनारायण कॉलोनी, लांथस क्लब के पीछे व आसपास के क्षेत्र में लोग पानी की गंभीर किल्लत से जूझ रहे हैं। स्थानीय निवासियों ने जिला कलेक्टर कार्यालय पर प्रदर्शन कर विभाग के अधिकारियों पर कई गंभीर आरोप लगाए। लोगों का कहना था कि जलदाय विभाग और चम्बल परियोजना के अधिकारी जिम्मेदारी लेने की बजाय एक-दूसरे पर आरोप मढ़ रहे हैं। शिकायतों के बावजूद कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। पाइप लाइन बिछाने के दावों के बीच आज भी पुरानी, जर्जर पाइपों से जल

■ **लोगों का कहना था कि जलदाय विभाग, चम्बल परियोजना के अधिकारी जिम्मेदारी लेने की बजाय एक-दूसरे पर आरोप मढ़ रहे हैं**

सप्लाई की जा रही है, जो वर्तमान जनसंख्या के हिसाब से अपर्याप्त है। जनता ने जिला प्रशासन से मांग की है कि कलेक्टर परिसर में जनसुनवाई के लिए एक विशेष कक्ष स्थापित किया जाए तथा एक हेल्पलाइन नंबर जारी कर आमजन की समस्याएँ सीधे अधिकारियों तक पहुँचाई जाए। जल संकट को देखते हुए नागरिकों ने चेतावा है कि यदि शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो वे आंदोलन करने को मजबूर होंगे। प्रशासन से त्वरित कार्रवाई की मांग की गई है।



लोगों ने कलेक्टर कार्यालय पर प्रदर्शन कर विभाग के अधिकारियों पर आरोप लगाए।

राशिफल शुक्रवार 16 मई, 2025	
	ज्येष्ठ मास, कृष्ण पक्ष, चतुर्थी तिथि, शुक्रवार, विक्रम संवत् 2082, मूल नक्षत्र दिन 4:08 तक, सिद्ध योग प्रातः 7:14 तक, बव करण सायं 4:38 तक, चन्द्रमा आज धनु राशि में संचार करेगा।
ग्रह स्थिति: सूर्य-वृष, चन्द्रमा-धनु, मंगल-कर्क, बुध-मेष, गुरु-मिथुन, शुक्र-मीन, शनि-मीन, राहु-मीन, केतु-कन्या राशि में।	
आज चतुर्थी व्रत है।	
श्रेष्ठ चौघड़िया: चर सूर्योदय से 7:23 तक, लाभ अमृत 7:23 से 10:43 तक, शुभ 12:23 से 2:03 तक, चर 5:23 से सूर्यास्त तक।	
राहूकाल: 10:30 से 12:00 तक। सूर्योदय 5:43, सूर्यास्त 7:03	

मेष	सिंह
 व्यावसायिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। नौकरपेशा व्यक्तियों को अतिरिक्त जिम्मेदारी मिल सकती है। आर्थिक मामलों में लापरवाही ठीक नहीं रहेगी।	 परिजनों के व्यवहार के कारण मन खिन्न हो सकता है। आवश्यक कार्यों के संबंध में दुविधा बनी रहेगी। खान-पान के कारण स्वास्थ्य खराब हो सकता है।

वृष	कन्या
 चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। मित्रों/रिश्तेदारों से अनबन हो सकती है। पारिवारिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है।	 घर-परिवार में सुख-नहीं है। मित्रों/रिश्तेदारों से अनबन हो सकती है। पारिवारिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है।

धनु	मकर
 व्यावसायिक कार्यों के संबंध में उचित सोच-विचार हो सकता है। महत्वपूर्ण कार्य योजना का क्रियान्वयन हो सकता है। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा।	 घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। पारिवारिक कारणों से तनाव बना रहेगा। अनर्गल कार्यों में समय खराब हो सकता है।

मिथुन	तुला
 परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिवार में शुभ-मौलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। आज परिजनों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है।	 व्यावसायिक कार्यों से संबंधित वार्ता सफल रहेगी। व्यावसायिक कार्यों में उचित सफलता मिलेगी। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे।

कर्क	वृश्चिक
 व्यक्तिगत परेशानियों से राहत मिल सकती है। दिनचर्या में सुधार होगा। विवादित मामलों का निपटारा हो सकता है। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।	 व्यावसायिक कार्यों से संबंधित संर्क बनेंगे। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। यात्रा का कार्यक्रम बन सकता है।

कुंभ	मीन
 आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। संभावित खोत से धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होने लगेंगी।	 व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बने लेंगे। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

टैंट गोदाम में भीषण आग लगने से 80 लाख का सामान जलकर राख हुआ

विराटनगर, बानसूर और कोटपुतली से फायर ब्रिगेड की तीन गाड़ियां पहुंची और आग बुझाई

नारायणपुर, (निसं)। कस्बे के बाइपास स्थित तहसील परिसर के पास गुरुवार सुबह लगभग पांच बजे एक टेंट गोदाम में अचानक भीषण आग लग गई। आग से लगभग 80 लाख रुपए का सामान जलकर राख हो गया। आग की लपटें इतनी तेज थी कि आसपास के क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने तुरंत टेंट मालिक राजेंद्र छिपी और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। घटना की गंभीरता को देखते हुए विराटनगर, बानसूर और कोटपुतली से फायर ब्रिगेड की तीन गाड़ियां मौके पर पहुंची। लगभग तीन घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन तब तक पूरा गोदाम जलकर राख हो चुका था।

भारी नुकसान, जल गई टेंट सामग्री :- टेंट मालिक राजेंद्र छिपी ने बताया कि गोदाम में 1600 कुर्सियां, 300 भगोने, 25 कूलर, 50 कढ़ाई, ओपन ट्रस्ट व झोपड़ी टेंट, बाल्टियां, बर्तन, रजाई, गद्दे, चांदनी, कपड़े सहित अन्य सामग्री रखी हुई थी। आग की तीव्रता इतनी अधिक थी कि सब



टेंट गोदाम में अचानक भीषण आग लगने से सामान जल गया।

कुछ पूरी तरह जल गया। आग से गोदाम की आरसीसी छत भी क्षतिग्रस्त हो गई। प्राथमिक आंकलन के अनुसार, लगभग 80 लाख रुपए का नुकसान हुआ है।

आग के कारणों पर संशय :- फिलहाल आग लगने के कारणों का स्पष्ट पता नहीं चल पाया है। टेंट मालिक ने बताया कि गोदाम में बिजली कनेक्शन भी नहीं था। इसके बावजूद

आग लगना रहस्य बना हुआ है। आशंका जताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट या किसी अन्य तकनीकी कारण से आग लगी हो सकती है। मौके पर थानाधिकारी ओमप्रकाश मौफा

■ गोदाम में 1600 कुर्सियां, 300 भगोने, 25 कूलर, 50 कढ़ाई, ओपन ट्रस्ट व झोपड़ी टेंट, बाल्टियां, बर्तन, रजाई, गद्दे, चांदनी, कपड़े सहित अन्य सामग्री जल गई

पुलिस जाट्टे सहित मौजूद रहे और स्थिति को संभाला।

इस घटना के बाद अलवर टेंट संगठन और स्थानीय ग्रामीणों ने एसडीएम को कलेक्टर के नाम जापन सौंपा। उन्होंने पीड़ित व्यवसायी को आर्थिक सहायता देने और नारायणपुर नगरपालिका में फायर ब्रिगेड की स्थायी व्यवस्था की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि अगर स्थानीय स्तर पर दमकल वाहन उपलब्ध होता, तो इतना बड़ा नुकसान रोका जा सकता था।

संस्था प्रधान को हटाने की मांग, तीसरे दिन भी धरना जारी

दो महिला अध्यापिकाओं की तबीयत बिगड़ी, जिला प्रमुख को ज्ञापन दिया



धरना स्थल पर महिला शिक्षकों की तबीयत बिगड़ गई।

सादुलपुर, (निसं)। पीएमश्री राजकीय मोहता बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय राजगढ़ के स्टाफ सदस्यों का धरना गुरुवार को सीबीईओ कार्यालय के सामने तीसरे दिन भी लगातार जारी रहा।

जानकारी के अनुसार इस मौके पर गर्मी के दौरान दो महिला अध्यापिकाओं की तबीयत भी बिगड़ गई। विद्यालय स्टाफ ने ब्लॉक शिक्षा अधिकारी बबलेश शर्मा को लिखित शिकायत कर बताया कि पीएमश्री राजकीय मोहता बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय राजगढ़ की प्राचार्य डॉ. सुशीला बलौदा द्वारा बरिष्ठ अध्यापक सुमेर सिंह के साथ थपड़

■ जिला प्रमुख वन्दना आर्य एवं पंचायत समिति प्रधान विनोद देवी ने धरना स्थल पर पहुंच शिक्षकों से मुलाकात की

मारने की घटना की सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच करने, स्टाफ सदस्यों के साथ लगातार हो रहे दुर्व्यवहार एवं शोषण की जांच करने, विभिन्न सरकारी योजनाओं में हुए गबन की जाँच तथा प्रधानाचार्य को विद्यालय से हटाने की मांग पूरी नहीं होने तक धरना जारी रहेगा। वही मांग को लेकर

जिला प्रमुख वन्दना आर्य एवं पंचायत समिति प्रधान विनोद देवी ने धरना स्थल पर पहुंच कर पीड़ित शिक्षकों से मुलाकात की तथा अविलम्ब कार्यवाही का आश्वासन दिया। इस मौके पर राधा यादव, प्रविता, संजु, अनिता देवी की तबीयत बिगड़ गयी। धरने पर सरपंच संघ के अध्यक्ष शीशराम पुनियां, राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत के उपशाखा राजगढ़ के अध्यक्ष महेंद्र सिंह पुनियां, सदीक खान, सेवानिवृत्त शारीरिक शिक्षक यासीन खां, प्रदेश संरक्षक ओमप्रकाश मुहाल, ब्लॉक प्रवक्ता नरेश राय, वीरेंद्र मोंडू व श्रीचंद आदि सहित विद्यालय के स्टाफ सदस्य धरने पर बैठे।

विवाहिता झुलसी

कोटपुतली, (निसं)। कस्बे के गढ़ कॉलोनी में गुरुवार दोपहर रसोई में खाना बनाते वक्त एलजीवी गैस सिलेंडर के रेग्युलेटर से गैस रिसाव के चलते एक विवाहिता के झुलस गई। ग्राम जैनपुरवास निवासी सोनिया पत्नी अंकित अपने परिवार सहित गढ़ कॉलोनी में किराये के मकान में निवास कर रही है। जहां रसोई में काम करते वक्त अचानक गैस रिसाव के कारण आग लग गई जिससे वह झुलस गई, जिसे उपचार के लिये राजकीय बीडीएम जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

उदयपुर में दो अलग-अलग हादसों में युवक व युवती की मौत

उदयपुर, (कासं)। शहर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र में कार की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई।

पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार शहर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र मादडी रोड पर कार की चपेट में आने से मोतीखेडा गुडली डबोक निवासी दिलिपसिंह पुत्र जयसिंह राजपूत की

मौत हो गई। रात में वह मादडी से प्रतापनगर की तरफ जा रहा था, जहां बीच रास्ते में हादसा हो गया। गंभीर घायल होने पर उसे उपचार के लिए उपकदमा दर्ज करने पर अड़े रहे। कपड़े उसकी मौत हो गई। सूचना पर एसएसआई अमरसिंह ने मृतक का पोस्टमार्टम करवा शव परिजनों को सौंपा।

युवती ने आत्महत्या की : उदयपुर शहर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र में युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार बुधवार सांय प्रतापनगर थाना क्षेत्र रेबारियों का गुडा निवासी दिक्षा सुखवाल (19) पुत्री महेंद्र सुखवाल ने अपने कमरे में फांसी लगा

आत्महत्या कर ली। इसकी सूचना मिलने पर परिजनों ने उसे चिकित्सालय पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। एसएसआईअमरसिंह ने मृतक का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंपा। प्रकरण की जांच हेड कांस्टेबल सज्जनसिंह करेंगे।

सोलर प्लांट लगाने की आड़ में खेजड़ी के पेड़ काटना जारी, लोगों में आक्रोश

नोखा दहिया, जयमलसर की रोही में 148 और राजासर में खेजड़ी के 120 पेड़ काट डाले

- नोखा दहिया, जयमलसर में एक बड़े सोलर प्लांट में पर्यावरण प्रेमियों ने दिनभर प्रदर्शन किया
- पर्यावरण प्रेमी सोलर कंपनी के मालिक और प्रतिनिधियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने पर अड़े रहे
- आत्मदाह करने की चेतावनी दी, गजनेर पुलिस पर्यावरण प्रेमी भोमाराम भादू को ले गई

बीकानेर, (निसं)। सोलर प्लांट लगाने की आड़ में राज्य वृक्ष खेजड़ी की बलि देने का काम बदस्तूर जारी है। राजासर की रोही में मंगलवार रात 120 पेड़ काट डाले। इसी प्रकार नोखा दहिया और जयमलसर की रोही में खेजड़ी के 148 पेड़ काटने की सूचना मिली है। विरोध करने पर एक पर्यावरण प्रेमी को पुलिस पकड़ कर ले गई।

बीकानेर तहसील के लाखूसर, कालासर, केला, राजासर गांव में सोलर प्लांट लगाने के लिए जमीनों की सफाई की जा रही है। पिछले दो-तीन महीने में 200 से अधिक पेड़ काट डाले। मंगलवार रात को राजासर में 120 पेड़ काटने की सूचना मिली है। इधर नोखा

दहिया और जयमलसर में एक बड़े सोलर प्लांट में पर्यावरण प्रेमियों ने दिनभर विरोध प्रदर्शन किया। नाल पुलिस की मदद से पर्यावरण प्रेमी सोलर प्लांट परिसर में घुसे। अंदर काफी संख्या में पेड़ कटे हुए मिले। सूचना मिलने पर गजनेर पुलिस, राजस्व तहसीलदार,

गिरदावर और पटवारी भी मौके पर पहुंच गए। पर्यावरण प्रेमी सोलर कंपनी के मालिक और प्रतिनिधियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने पर अड़े रहे। कपड़े उतारकर तेज धूप में धरने पर बैठ गए। आत्मदाह करने की चेतावनी दे डाली। विवाद बढ़ते देख गजनेर पुलिस

पर्यावरण प्रेमी भोमाराम भादू को पकड़ कर ले गई। उन्हें शांतिभर करने के आरोप में गिरफ्तार कर बाद में जमानत पर छोड़ दिया गया।

जीव रक्षा संस्था के अध्यक्ष मोखराम बिशोई ने बताया कि प्लांट के पीछे रास्ता है, जहां से कटे हुए पेड़ों का परिवहन किया जाता है। इसका ठेका एक वन माफिया को दिया हुआ है। बार-बार कहने के बाद भी तहसीलदार ने सोलर प्लांट मालिक, प्रतिनिधि और वन माफिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं कराया। धारणिया का आरोप है कि जिला प्रशासन सोलर कंपनियों के दबाव में है। अधिकारियों को मुकदमा दर्ज कराने के लिए मना किया हुआ है। प्लांट

में घटना के दौरान पर्यावरण प्रेमी जीआर गोदारा, सुभाष प्यिशोई, कानाराम गोदारा भी मौके पर मौजूद थे।

राजासर गांव में खेजड़ी के 120 पेड़ और काटे जाने की सूचना मिली है। पर्यावरण प्रेमियों ने बताया कि देर रात 12 बजे से लेकर सुबह चार बजे तक पेड़ों पर आरियां चलती रही। सूचना मिलने पर छत्तारगढ़ पुलिस बुधवार सुबह मौके पर पहुंची। ग्रामीणों ने बताया कि ज्यादातर पेड़ रातोंरात ही गायब कर दिए गए।

एसएचओ भजनलाल ने बताया कि खेजड़ी के पेड़ों से लदी दो पिकअप गाड़ी सौंच की है। आरोपियों के खिलाफ वन अधिनियम और चोरी का मुकदमा दर्ज किया है।

1500 रु. की रिश्वत लेते सहायक उपनिरीक्षक गिरफ्तार

करौली, (निसं)। एसीबी मुख्यालय के निदेश पर एसीबी करौली ईकाई द्वारा गुरुवार को कार्रवाई करते हुये सीताराम सहायक उप निरीक्षक पुलिस इंचार्ज पुलिस चौकी कस्बा टोडाभीम को परिवादी से 1500 रुपये रिश्वत राशि लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक पुलिस डॉ. रवि प्रकाश मेहरडा ने बताया कि एसीबी चौकी करौली को एक शिकायत मिली कि परिवादी से उसके द्वारा मारपीट के दर्ज कराये मुकदमे में परिवादी की मदद करने एवं मुलाजिमी को पकड़कर उनका चालान करने की एवज में फाईल चार्ज



आरोपी सहायक उपनिरीक्षक सीताराम।

के नाम पर रिश्वत राशि 1500 रुपये की मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी भरतपुर रेंज के उप महानिरीक्षक पुलिस राजेश सिंह के सुपरविजन में जगदीश पाट्टाज पुलिस निरीक्षक एसीबी करौली द्वारा ट्रेप कार्रवाई करते हुये सीताराम सहायक, उप निरीक्षक पुलिस इंचार्ज पुलिस चौकी कस्बा टोडाभीम को परिवादी से 1500 रुपये रिश्वत राशि लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। एसीबी की अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस रिमता श्रीवास्तव के सुपरविजन में आरोपी से पूछताछ तथा कार्रवाई जारी है। एसीबी. द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जाएगा।

पावटा के कई वार्डों में पेयजल संकट गहराया

पानी की टंकी में पानी चढ़ाने वाला मोटर पंप का मोनोब्लॉक खराब होने से परेशानी हुई

■ ‘लोगों को टैंकरों के माध्यम से पानी भेजा जा रहा है’

पावटा, (निसं)। पीएचइडी विभाग के पावटा कस्बे के शमशान घाट स्थित पानी की टंकी में पानी चढ़ाने वाला मोटर पंप का मोनोब्लॉक खराब होने के कारण पावटा कस्बे के कई वार्डों में पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है।

जलदाय विभाग के कनिष्ठ अभियंता दयाराम चौधरी ने बताया कि पंपहाऊस का मोनोब्लॉक जल गया है जिसके चलते पानी की आपूर्ति बाधित हुई है। मोनोब्लॉक को देर रात टीम द्वारा ठीक करवाया गया लेकिन वह फिर जल गया। जल्द ही लोगों को पानी की आपूर्ति शुरू की जाएगी। सभी वार्डों में पेयजल आपूर्ति के प्रयास किए गए हैं।

जिन वार्डों में पानी की आपूर्ति नहीं हुई,

वहां टैंकरों से पानी भिजवाया गया है। स्थानों पर लोगों को टैंकर से पानी भेजा जा रहा है।

लोगों का कहना है कि टैंकर का पानी पर्याप्त नहीं रहता जिससे घर का सभी काम नहीं हो पाता है। वार्डों में एक टैंकर पानी से लोगों का गुजारा नहीं हो पा रहा है। लोगों ने कहा कि अगर पुराने मोटर पंप बनाने के बजाए नए मोटर पंप लगा दिया जाए तो बार-बार लोगों को पानी के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। उन्होंने विभाग से समस्या को स्थायी समाधान करने की मांग की है। सुझाव भी दिया है कि यदि कभी ऐसी समस्या पैदा आती है तो अन्यत्र पेयजल योजना के माध्यम से वार्डों में पानी की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। वहीं लोगों ने आग्रह किया है कि भीषण गर्मी को देखते हुए समस्या का हल जल्द किया जाए।

<

राजस्थान सरकार

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग

प्रथम तल, स्वास्थ्य भवन, भीनमाल रोड, जालोर

क्रमांक: अ.अ./चि.एच.स्वा/2025-26/321-329

दिनांक: 03.05.2025

ई-निविदा सूचना संख्या 06/2025-26

राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से इस खण्ड के अन्तर्गत विभिन्न चिकित्सालयों पर रु. 140.37 लाख का 1 सिविल कार्य हेतु उभयवृत्त श्रेणी में सर्वजनिक निर्माण विभाग एवं राज्य सरकार / केन्द्रीय सरकार के अधिकृत एजेंटों / केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग / डाक एवं दूर संचार विभाग/ रेवेन इत्यादि में पंजीकृत संवेद्यकों के समकक्ष हो, से निर्माण कार्य हेतु निविदा प्रारंभ में ई-टेंडरिंग प्रक्रिया ऑन लाईन निविदाये आमंत्रित की जाती है। निविदा से संबंधित जानकारी हेतुआइटीआर की वेबसाईट WWW.dipronline.org http://eproc.rajjasthan.gov.in व विभागीय वेबसाईट <http://rajjswasthyha.nic.in> पर देखा जा सकता है। **NIB No. MHS2526A0387**

1. **MHS2526WSOB00728**

(विनोद कुमार स्वामी)

अधिशाषी अभियन्ता

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, जालोर

DIPR/C/6110/2025

कार्यालय नगरपालिका मण्डल, सुमेरपुर, जिला - पाली			
क्रमांक : न.पा.सु/विकास/ई-निविदा/2025-26/1181		दिनांक 14.05.2025	
-: ई-निविदा 06/2025-26 सूचना :-			
नगरपालिका मण्डल, सुमेरपुर की ओर से मायता प्राप्त पंजीकृत ठेकेदारों से निविदा द्वारा 01 विकास कार्यों की कुल लागत 14.22 लाख रुपये की निविदा आमंत्रित की जाती है। आंशिक अथवा पूर्णतः निविदा स्वीकृत/ अस्वीकृत करने का अधिकार ई-निविदा स्वीकृत अधिकारी को होगा। ई-निविदा की विस्तृत जानकारी व शर्त कार्यालय में एवं विभाग की वेब साईट www.sppp.rajjasthan.gov.in एवं www.eproc.rajjasthan.gov.in पर देखी व पढ़ी जा सकती है।			
जिनके UBN No. निम्नलिखित है:- 1-DLB2526WSOB04753			
Bid Selling Last Date		प्रशासक नगरपालिका, सुमेरपुर	अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका, सुमेरपुर
राज.संवाद/सी/25/2368			

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड			
कार्यालय अधीन अधिनियम (आर डी एस एल)			
प्रमाणित कॉपी सूचना: पुराना पॉवर हाउस, बनीमाल, जयपुर, टेलीफोन: 0141-2201022 ई मेल: sardas@jvvn.org			
ई - निविदा सूचना			
जयपुर डिस्कॉप के अन्तर्गत विभिन्न वृत्तों में आरडीएसएल के अंतर्गत टर्न की आधार पर बचे हुए अविद्युतिकृत घरों के विद्युतिकरण कार्य के लिए सामग्री / उपकरणों की आपूर्ति, निर्माण, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग के तहत निविदादाताओं से TN-593 के लिए ई-निविदा तीन भागों में (तकनीकी, वाणिज्यिक एवं वित्तीय) आमंत्रित की जाती है। योग्य निविदादाता सम्पूर्ण निविदा सम्बन्धित दस्तावेज ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल http://www.eproc.rajjasthan.gov.in पर दिनांक 13.05.2025 से डाउनलोड कर सकते है। निविदाएं ऑनलाईन ई-पोर्टल पर दिनांक 10.06.2025 को सांय 5.00 बजे तक ही स्वीकार की जायेगी। निविदा सम्बन्धी जानकारी, कार्य का विवरण इत्यादि जयपुर विद्युत वितरण निगम की वेबसाईट http://energy.rajjasthan.gov.in/jvvn/ , http://www.sppp.rajjasthan.gov.in पर देखा जा सकता है। UBN: VVN2526WLOB00023 कॉलैक्ट- 2993 (2025) अधीन अधिनियम (आर डी एस एल)			
राज.संवाद/सी/25/2349 विनीत विक्रमजी के लिए टेंडर की नमूना 1800 180 6507			

